

न्यूनतम सांझी समझ

□ रोहित धनकर

पिछली बार हमने शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं के सांझे प्रयासों के लिए एक प्रस्ताव रखा था । इसमें यह भी कहा गया था कि सांझा कार्यवाही का आधार एक पारस्परिक न्यूनतम सांझी सैद्धांतिक समझ हो सकती है । हमें लगा कि इस सांझी समझ पर भी कुछ चर्चा करनी चाहिये । इस प्रस्ताव पर हम 'शिक्षा विमर्श' में खुला संवाद आमंत्रित करते हैं । हमें लगता है कि शिक्षा में बेहतर विकल्प की तलाश करने वाले सभी लोग सामाजिक बदलाव की आवश्यकता अनुभव करते हैं एवं उसी से प्रेरित भी होते हैं । हमारा यह भी मानना है कि मूलतः कोई भी शैक्षिक उपक्रम अधिक न्यायपूर्ण समाज की रचना की दिशा में ही देखा जाता है । इसका आशय यह है कि इस तरह का काम करने वाले लोगों का समाज एवं शिक्षा को लेकर एक सैद्धांतिक आधार तो है तथा उसमें यथेष्ट उभय बिन्दु भी हैं । इन्हीं उभय बिन्दुओं को एकत्रित कर देने से सांझी समझ बन सकती है । अतः वास्तव में यह सांझी समझ बनाने का नहीं उसकी स्वीकार्य अभिव्यक्ति का सवाल अधिक है । अतः मूल सैद्धांतिक ढांचे की आधिकारिक अभिव्यक्ति तो नेटवर्क में शामिल संस्थाओं के लोग साथ बैठकर, गंभीर विमर्श के बाद ही कर सकते हैं । यहां तो हम उस विमर्श के लिए कुछ प्रस्थान बिन्दु ही सुझा सकते हैं ।

शिक्षा के उद्देश्य

□ व्यक्ति में निर्णय की विवेकपूर्ण स्वायत्तता एवं कर्म के स्वावलम्बन का विकास करना ।

- विवेकपूर्ण स्वायत्तता के लिए समझ का विकास एवं समालोचनात्मक चिंतन का विकास आवश्यक है ।
- विवेकपूर्ण स्वायत्तता का आशय आत्मकेन्द्रित स्वार्थपूर्ण चिंतन नहीं अन्य सभी की स्वायत्तता का स्वीकार है ।
- इसके लिए संवेदनशीलता एवं नैतिक विकास आवश्यक है ।
- कर्म का स्वावलम्बन भी समझ एवं समालोचनात्मक चिंतन की तरह स्वायत्तता की आवश्यक शर्त है ।
- कर्म का स्वावलम्बन कौशलों के विकास की मांग करता है ।
- कौशलों का विकास पदार्थ संबंधी ज्ञान, कल्पनाशीलता, समस्या समाधान एवं शारीरिक दक्षताओं पर निर्भर करता है ।

हम किन बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं ?

- जिस तरह की शिक्षा की हम बात कर रहे हैं वह भारत के प्रत्येक बच्चे का अधिकार है ।
- जनतांत्रिक समाज के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक शिक्षा भेदभाव के साथ नहीं मिल सकती । अतः शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य समान होने आवश्यक हैं ।

- सभी शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं उनके लिए संसाधनों का प्रावधान समान होना भी जनतांत्रिक समाज के लिए शिक्षा की आवश्यक तार्किक निष्पत्ति है ।

शिक्षाक्रम

- विवेकपूर्ण स्वतंत्रता के लिए समझ एवं समालोचनात्मक चिंतन का विकास आवश्यक है ।
- समझ में ज्ञान, सूचना एवं सौंदर्य बोध के पक्ष समाहित हैं ।
 - इसके लिए संवेदनात्मक एवं नैतिक विकास भी आवश्यक है ।
 - संवेदनात्मक एवं नैतिक विकास को समझ के विकास का हिस्सा भी माना जा सकता है पर इस पर यथेष्ट बल देने के लिए यहां पृथक जिक्र किया है ।
 - विवेक पूर्ण स्वायत्तता के लिए कर्म में स्वावलंबन भी आवश्यक है ।
 - कर्म के लिए समझ एवं समझ के बिना कर्म की कुशलता का विकास संभव नहीं है ।
 - कर्म का स्वावलंबन कौशलों के विकास की मांग करता है ।
 - कौशलों का विकास पदार्थ संबंधी ज्ञान, कल्पनाशीलता, समस्या समाधान एवं शारीरिक दक्षताओं पर निर्भर करता है ।
- अविवेचित ज्ञान का तैयार उत्पाद के रूप में हस्तांतरण, समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा हो सकता है ।
- नैतिक मूल्यों का अंतिम सत्य के रूप में रूढ़ प्रस्थापन समालोचनात्मक चिंतन को समाप्त कर देता है ।
 - अतः समझ एवं नैतिक मूल्यों का विकास समालोचनात्मक चिंतन के साथ साथ होना आवश्यक है ।
 - कर्म कौशलों के विकास में अधिकतम खुलापन एवं व्यापकता स्वावलंबन में मददगार होगी ।
- समझ (ज्ञान, सूचना, बौद्धिक दक्षतायें) एवं कौशलों का विकास अपने अनुभवों का विश्लेषण एवं उन्हें व्यवस्थित करने से ही होता है ।
- बच्चे के अनुभव अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए एवं समस्याओं को हल करने के प्रयत्नों में ही विश्लेषित एवं व्यवस्थित होते हैं ।
 - स्थानीय अनुभव के विश्लेषण एवं व्यवस्थापन में अवधाणाओं का सामान्यीकरण होता है जो धीरे-धीरे स्थान-निरपेक्ष होकर सार्वभौम उपयोग की तरफ बढ़ता है ।
 - अतः शिक्षाक्रम का आरंभ अब और यहां से ही हो सकता है पर उसकी दिशा सार्वभौम ही होनी चाहिये ।
- समझ एवं कौशलों के विकास में तार्किक क्रम हो सकता है ।
- समझ एवं कौशलों के विकास में मनोवैज्ञानिक क्रम भी हो सकता है ।
 - शिक्षाक्रम के बहुत से क्षेत्रों में यह क्रम बहुत दृढ़ एवं बाध्यकारी न हो ऐसा संभव है ।
 - अतः क्रम पर उतना ही बल दिया जाना चाहिये जो तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से आवश्यक है । उससे अधिक बल शिक्षाक्रम को जड़ बना सकता है ।
- शिक्षाक्रम में समावेश के लिए चीजों (अवधारणाओं, सूचनाओं, क्षमताओं, दक्षताओं, रुझानों, मूल्यों, कौशलों आदि) का चुनाव उपरोक्त बिन्दुओं से संगत रहना चाहिये ।
- शिक्षाक्रम में समाविष्ट चीजों की क्रम व्यवस्था भी उपरोक्त सिद्धांतों से संगत होनी चाहिये ।

शिक्षण विधि

- शिक्षण विधियां सीखने के मनोविज्ञान से सम्मत होनी चाहियें ।
- वे स्वायत्तता एवं समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाली होनी चाहियें ।
- वे बच्चे की स्वतंत्रता व मानवीय गरिमा का सम्मान करने वाली होनी चाहियें ।
- प्रताड़ना, भय, लालच एवं बल प्रयोग पर आधारित नहीं होनी चाहियें ।
- लोकतंत्र के लिए उपयुक्त शिक्षा के लिए आवश्यक है कि वह एक लोकतांत्रिक माहौल में ही सम्पन्न हो ।
अतः विद्यालय का माहौल लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करने वाला होना चाहिये ।

शिक्षा के लिए उत्तरदायित्व

- लोकतंत्र का विचार मानवीय गरिमा, समता, उनके लिए प्रतिबद्धता, सत्ता तथा संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे एवं समुचित उपयोग के विचारों पर आधारित है ।
- समाज में इन मूल्यों की व्यापक स्वीकृति व्यवस्थाओं (सरकार आदि) को लोकतांत्रिक बनाती है ।
- अतः राज्य का अपने आप को लोकतांत्रिक घोषित करना समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यापकता एवं उनके लिए प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है ।
- जो राज्य अपने आप को लोकतांत्रिक घोषित करता है उसकी तार्किक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित करे ।
- लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी निर्णय की स्वायत्तता एवं कर्म के स्वावलंबन की मांग करती है ।
- मानव स्वायत्तता एवं कर्म के स्वावलंबन की क्षमता प्राप्त करने की संभावनाओं से युक्त पैदा होता है, पर ये क्षमतायें विकसित तो शिक्षा से ही होती हैं ।
- अतः लोकतंत्र के लिए उपयुक्त शिक्षा सबको मिले यह राज्य की जिम्मेदारी है ।
- राज्य सत्ता लोकतंत्र की तरफ लोक के दबाव में ही बढ़ती है ।
- अतः लोकतंत्र के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था भी लोक के दबाव में ही संभव है ।
- यदि शिक्षा को उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप होना है तो उसकी व्यवस्था का भी लोकतांत्रिकरण आवश्यक है । अर्थात् वह पूरी तरह राज्य कर्मचारियों के अधिकार में नहीं रह सकती ।
- परिणाम स्वरूप कह सकते हैं : शिक्षा के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना राज्य का काम है । शिक्षा का स्वरूप, गुणवत्ता एवं क्रियान्विति के तरीके समाज के अधिकार क्षेत्र में रहने चाहियें । राज्य इसमें सहयोग से इनकार नहीं कर सकता ।

संक्षेप में :

लोकतंत्र के लिए शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण । ◆